उत्तर–प्रदेश विधान सभा निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में जातिगत दबाव समूह की भूमिका (1989 – 1995)

डॉ0 रत्ना सिन्हा
प्रवक्ता राजनीति विज्ञान
प्रकाश विद्यामंदिर महिला महाविद्यालय
कानपुर।

सारांश

सामाजिक एवं आधुनिकीकरण के मार्ग में एक बड़ा अवरोध होने के बावजूद भी भारतीय राजनीति में जाति एक महत्वपूर्ण तत्व रहा है। राजनीति में जातियों की महत्वपूर्ण स्थिति का अन्तर्निहित तत्व राजनीतिक दलों द्वारा जाति के आधार पर सत्ता प्राप्ति की आकांक्षा है। अतः जातियाँ राजनीतिक दलों के माध्यम से चुनाव को प्रभावित करना चाहती हैं। वर्ष 1989 से 1995 के काल में उ0प्र0 विधान सभा निर्वाचन में जातिगत दबाव समूह की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इस काल में राजनीति, शिक्षा, प्रशासन सभी जाति से अभिप्रेरित रहे।

मूल शब्द : विधानसभा निर्वाचन, जातिगत दबाव समूह, 1989–1995, उ0प्र0।

उत्तर प्रदेश केन्द्रीय राजनीति का गढ़ माना जाता है। यहां होने वाले चुनावों का देश की राजनीति पर दूरगामी प्रभाव होना निश्चित ही है। 1989–1995 के 6 वर्षों के काल ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक नवीन मोड़ प्रदान किया है। इस काल में उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण रही। जातियां अपने हितों के प्रति पूर्व की अपेक्षा अधिक सचेत रही। यह सचेतनता पिछड़ी एवं दलित जातियों में अधिक दिखी। जातियों का यही प्रयास रहा कि वही राजनीतिक दल सत्ता में आये जो उनके हितों की रक्षा करें। अतः राजनीति दलों ने जातियों को उनके हितों के अनुरूप प्रभावित करने का प्रयास किया। प्रो0 मौरिस जोन्स के शब्दों में ''मुख्य खोज यह है कि जातियों के लिए राजनीति अधिक महत्वपूर्ण है तथा राजनीति में जातियां पहले की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हैं।''[1]

राजनीतिक दलों का यह प्रयास न केवल निर्वाचन के पूर्व, बल्कि निर्वाचन के दौरान एवं सत्ता में आने पर भी दिखा। जिसे इस काल में हुये विधानसभा चुनावों के संदर्भ में भली–भांति प्रकार से समझा जा सकता है।

इस काल के प्रथम आम चुनाव 1989 में निर्वाचन के पूर्व प्रदेश की राजनीति में सक्रिय सभी राजनीतिक दलों जनतादल – बसपा – भाजपा – कांग्रेस ने जातिगत समीकरण के आधार पर ही सीटों का आवंटन किया। जनता दल ने मुसलमानों, पिछड़ी एवं दलित जातियों में अधिक सीटें आवंटित कीं। बसपा (बहुजन समाज पार्टी) जो कि दलितों की पार्टी है, उसने भी सर्वाधिक सीटें दलितों में आवंटित की हैं। इसके अतिरिक्त कांग्रेस भी पिछड़ी एवं दलित जातियों (जो कि कांग्रेस के परम्परागत वोट बैंक थे) को अपने पक्ष में करने के लिए प्रयासरत थी, जबकि भाजपा ने सवर्णों विशेष रूप से ब्राम्हणों) में अधिक सीटें आवंटित की। इन राजनीतिक दलों के नारे, मुद्दे एवं जनसभाओं तथा रैलियों में दिये गये भाषण भी जातिगत भावनाओं को उभारने वाले थे। इस चुनाव में जनतादल के 'आरक्षण' के मुद्दे ने पिछड़ी एवं दलित जातियों को सर्वाधिक प्रभावित किया। अतः 'आरक्षण' के मुद्दे के माध्यम से जहां जनता दल ने पिछड़ी एवं दलित जातियों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया वहीं मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए अयोध्या में मस्जिद तोड़ने का विरोध किया। आरक्षण के मुद्दे पर पिछड़ी एवं दलित जातियों की सशक्त भूमिका का ही परिणाम था कि 1977 के पश्चात् 1989 के चुनाव में सफलता प्राप्त कर जनता दल ने प्रदेश की सत्ता पर अपना वर्चस्व कायम किया। दलित जातियों का जनता दल के पक्ष में झुकाव होने के कारण बसपा को अधिक सफलता नहीं मिली। यद्यपि सवर्ण जातियों ने आरक्षण के मुद्दे का विरोध कर भाजपा के 'राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद' के मुद्दे का समर्थन किया परन्तु आरक्षण के मुद्दे के समक्ष भाजपा का 'राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद' का मुद्दा अधिक कारगर सिद्ध नहीं हुआ क्योंकि प्रदेश की राजनीति में इस बार पिछड़ी एवं दलित जातियों की भूमिका सशक्त दबाव समूह के रूप में थी तथा मुस्लिम वर्ग ने भी जनता दल के पक्ष में मतदान किया था। इस प्रकार इस चुनाव ने यह स्पष्ट किया कि केवल सवर्ण मतों के आधार पर प्रदेश की सत्ता पर अपना वर्चस्व कायम करना सम्भव नहीं है। अतः भाजपा ने पिछड़ी एवं दलित जातियों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया।

1991 के चुनाव में पूर्व (1989) की भांति ही सभी राजनीतिक दलों ने निर्वाचन से पूर्व सीटों का आवंटन जातिगत समीकरण को ध्यान में रखकर किया। पिछले चुनाव में पिछड़ी एवं दलित जातियों की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण सपा (1989 के चुनाव में मुलायम सिंह जनता दल में थे परन्तु 1991 में उन्होंने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा)। के अतिरिक्त भाजपा ने भी पिछड़ी एवं दलित जातियों को अपने पक्ष में करने के उद्देश्य से इन जातियों में अधिक सीटें आवंटित की, जबकि बसपा दलित जातियों को अपने पक्ष में करने के लिए प्रयासरत थी। अतः इस उद्देश्य से उसने अधिकांश सीटें दलित जातियों में ही आवंटित की।

कांग्रेस का जातिगत आधार कमजोर हो चुका था। अतः उसने मुसलमानों के अतिरिक्त सवर्ण, पिछड़ी एवं दलित जातियों में जातिगत समीकरण के आधार पर सीटें आवंटित की। इस चुनाव में सपा एवं भाजपा ने धर्म एवं सम्प्रदाय के आधार पर तीखे एवं जोशीले नारों का प्रयोग किया। भाजपा के नारे एवं जनसभाओं तथा रैलियों में दिये गये भाषण जहां हिन्दुओं की भावनाओं को उद्वेलित करने वाले थे, वहीं सपा के नारे मुसलमानों की भावनाओं को उभारने वाले थे। इस चुनाव में भाजपा एवं सपा में विशेष रूप से प्रतिद्वन्दिता दिखी। बसपा ने अपनी रैलियों एवं जनसभाओं में दलितों की भावनाओं को उभारने का प्रयास किया। इस उद्देश्य से उसने भाजपा एवं सपा दोनों की खुलकर आलोचना की। इस चुनाव में भाजपा के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मुद्दे का यद्यपि मुस्लिम सम्प्रदाय ने विरोध किया और सपा के पक्ष में मतदान किया परन्तु भाजपा के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर पिछड़ी, दलित एवं सवर्ण जातियों की सशक्त भूमिका का ही परिणाम था कि प्रदेश की सत्ता पर पहली बार भाजपा ने अपना वर्चस्व कायम किया।

1993 के चुनाव में 1989 एवं 1991 के चुनावों की अपेक्षा जातीय पहलू अधिक महत्वपूर्ण रहा। इस चुनाव में राजनीतिक दलों के पास नारे एवं मुद्दों का अभाव दिखा। अतः राजनीतिक दलों ने जातिगत समीकरण का विशेष ध्यान रखा। स्पष्ट है कि भारतीय राजनीति में जाति एक महत्वपूर्ण तत्व रहा है। जैसा कि डॉ0 रजनी कोठारी का अभिमत है। ''कोई भी सामाजिक तत्व पूर्णतया समाप्त नहीं हो सकता। अतः यह प्रश्न करना कि क्या भारत में जाति का लोप हो रहा है। अर्थशून्य है।[2]

इस चुनाव में सबसे अधिक प्रतिद्वन्दिता भाजपा एवं सपा में दिखी और दोनों राजनीतिक दलों ने एक–दूसरे को पराजित करने का प्रयास किया। इस उद्देश्य से सपा ने बसपा के साथ गठबंधन भी किया। 1991 के चुनाव में पिछड़ी एवं दलित जातियों ने भाजपा के 'राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद' के मुद्दे पर भावना के आधार पर मतदान किया था परन्तु शीघ्र ही उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि भाजपा में उनके हितों की रक्षा असम्भव है। अतः पिछड़ी जातियों का झुकाव सपा एवं दलित जातियों का झुकाव बसपा की ओर हुआ। इसके अतिरिक्त अयोध्या में मस्जिद विध्वंस के पश्चात् मुस्लिम सम्प्रदाय भाजपा से नाराज था। उसका यही प्रयास रहा कि किसी भी कीमत पर भाजपा पुनः सत्ता में न आने पाये। अतः भाजपा के लिये स्थिति पूर्व कि अपेक्षा अधिक चुनौतीपूर्ण थी। भाजपा ने सपा के जातिगत समीकरण को ध्वस्त करने के उद्देश्य से पिछड़ी जातियों (विशेषरूप से यादवों) में अधिक से अधिक सीटें आवंटित की तथा साथ में मुसलमानों को भी अपने पक्ष में करने का प्रयास किया, ताकि सपा का पिछड़ा मुसलमान समीकरण सफल न हो पाये। वहीं सपा ने भाजपा के जातिगत समीकरण को ध्वस्त करने के उद्देश्य से यादवों एवं दलित जातियों के अतिरिक्त गैर यादवों तथा मुसलमानों में भी सीटें आवंटित की। इस चुनाव में मुसलमान एवं पिछड़ी जातियों का सपा तथा दलित जातियों का बसपा की ओर झुकाव का परिणाम था कि भाजपा को विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ी। यद्यपि चुनाव में भाजपा को सबसे अधिक सीटें मिली परन्तु सपा–बसपा गठबंधन से सपा की सरकार बनी।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जनता दल के मुख्यमंत्री ने 'आरक्षण' के माध्यम से पिछड़ी जातियों का एवं 'राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद' के मुद्दे पर मुसलमानों का पक्ष लेकर उनका समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया, जबकि भाजपा ने अयोध्या में मस्जिद के स्थान पर मन्दिर के निर्माण का आह्वान कर हिन्दुओं का समर्थन प्राप्त करना चाहा तथा बसपा ने दलितों को उनके सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक अधिकारों के प्रति सचेत कराया, परिणामस्वरूप राजनीति में दलित जातियां सशक्त दबाव समूह के रूप में कार्य करने लगी तथा पूर्व की भांति अब उन्हें मौन वोट बैंक नहीं माना जाता है। सपा ने अपने शासनकाल में जहां राजनीति का यादवीकरण करने का प्रयास किया वहीं भाजपा ने राजनीति का ब्राम्हणीकरण एवं बसपा ने राजनीति का दलितीकरण करने का प्रयास किया। राज्यों की राजनीति में जाति की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण टिंकर जैसे विद्वानों ने राज्यों की राजनीति को जातियों की राजनीति की संज्ञा दी हैं।[3] 1989–1995 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव टिंकर के इस कथन को सार्थक स्वरूप प्रदान करते हैं।

पांच वर्ष की निरन्तर अस्थिरता की दृष्टि से भी भारतीय राजनीति में यह एक ऐतिहासिक समय रहा है। सन् 1967 से भारतीय राजनीति में बदलाव का यह चौथा महत्वपूर्ण पड़ाव है जो वैचारिक अधिक दलगत कम है।

इस प्रकार यह काल (1989–1995) विशिष्ट राजनीतिक विलक्षणताओं से परिपूर्ण रहा है।

1. इस काल में सवर्ण राजनीति को अवर्णों की खुली चुनौती के रूप में देखा जा सकता है।
2. इस काल में कांग्रेस को पहली बार तमिलनाडु और केरल की भांति उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन के लिए मजबूर होना पड़ा।
3. राज्य में क्षेत्रीय दलों की सरकार बनी।
4. राजनीति, प्रशासन एवं शिक्षा सभी जाति से अभिप्रेरित रहे।
5. राजनीतिक अस्थिरता की दृष्टि से भी यह काल महत्वपूर्ण रहा।
6. दलित चेतना का अभ्युदय इस काल की आश्चर्यजनक विशेषता रही।
7. पहली बार उ0प्र0 में दलित महिला मुख्यमंत्री बनी।

सन्दर्भ सूची :

1. Jones, Morris, Indian Government and Politics, quoted Rastogi, P. Indian Political system, Sushil Prakashan Meerut, 1992-93, Pg. 141
2. Kothari, Rajni, Caste In India Politics, Orient Langman, New Delhi 1970, P.-4
3. टिंकर उद्घृत फाड़िया बी0एल0 एवं जैन पुखराज, भारतीय शासन एवं राजनीति पृ0 631